

11. वेरावल में आटो एक्सचेंज स्थापित करना

**Export deal with China for pig Iron by SAIL**

3110. SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an export deal with China has been finalised for export of pig Iron by SAIL of India Limited;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether China has imposed condition that the Iron should be of a particular Steel Plant in India; and

(d) if so, the details thereof and the time schedule for completion of total export of the deal ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). It will not be in the commercial interest of the country to disclose further details of this export deal, except to mention that China has not imposed any condition that the pig iron should be from any particular steel plant.

**बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976**

**श्री बीड़ी श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम का राज्यों द्वारा क्रियान्वयन**

3111. श्री गोविन्द राम मिरी : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष संसद् द्वारा पारित बीड़ी श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम और बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में लिया है ;

उपस्कर की भारी कमी के कारण आशा है कि वेरावल एक्सचेंज को आटोमैटिक बनाने में समय लगेगा ।

(ख) यदि हां, तो उसका आधार क्या है, विशेष रूप से उस परिस्थिति में जब कि बीड़ी उद्योग में औद्योगिक सम्बन्धों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी हुई है ;

(ग) क्या सभी उद्योग, जिनमें वे अब तक श्रमिक कल्याण निधि स्थापना की गई है केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के अधीन आते हैं जब कि बीड़ी उद्योग पूर्णतः राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार इन दोनों अधिनियमों के क्रियान्वयन के कार्य को राज्य सरकारों को सौंपने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

**श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) :** (क) जी, हां ।

(ख) संसद् द्वारा पारित किए गए अधिनियमों को लागू करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है । इसलिए बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि की व्यवस्था भी केन्द्रीय सरकार कर रही है ।

(ग) : औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसी खानों, जिनके लिए कल्याण निधियां स्थापित की जाती हैं, केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आती हैं । बीड़ी तथा सिंगार श्रमिक (रोजगार की शर्तों) अधिनियम, 1966 राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है ?

(घ) इन अधिनियमों के कार्यान्वयन के काम को राज्य सरकारों को सौंपने का कोई विचार नहीं है ।